संपादकीय

निर्णय पुनरूत्थान अथवा विनाश हेतु

वर्षों पूर्व बीएसएनएल ने बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रमों को सरकार को इस आशा के साथ वापस कर दिया था कि उसके द्व ारा जमा धन राशि रूपया 67,00/– करोड़ की वापसी होगी। यह यूपीए–II सरकार के समय हुआ था क्योंकि उस समय कम्पनी की आर्थिक दशा संकट ग्रसित थी। अधिक समय व्यतीत हो गया परंतु रूपए की वापसी सरकार द्वारा नहीं की गई है। इस स्थिति में कम्पनी लाइसेंस फीस भुगतान करने में असमर्थ हो गई तथा कुछ धनराशि का समायोजन लाइसेंस फीस द्वारा किया गया। परन्तु वर्तमान में भी बीएसएनएल का लगभग रूपया 5,000/– करोड़ अब भी सरकार के पास है जिसकी वापसी होनी चाहिए।

मौजूदा संचार मंत्री द्वारा अनेकों बार संसद के भीतर तथा बाहर बुलंद आवाज में घोषणाएं हुई है कि एनडीए सरकार यूपीए–II से भिन्न है तथा बीएसएनएल के पुनर्जीवन के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। घोषणाएं केवल घोषणाएं ही रही तथा सरकार ने सरकारी उपक्रम के पुनर्जीवन हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की एवं न ही स्पेक्ट्रम के पैसे लौटाये। परंतु अब समाचार पत्रों में निराशाजनक सूचनाएं इस आशय के प्रकाशित हुए हैं कि भारत सरकार के कैबिनेट ने 5 अगस्त को बीएसएनएल को सीडीएमए स्पेक्ट्रम मूल्य का केवल रू. 196.16 करोड़ भुगतान करने का निर्णय लिया है। बीएसएनएल को आर्थिक सहायता देने की बात तो दूर सरकार द्वारा उसकी ***जमा धन राशि की वापसी भी नहीं हो रही है। यह रवैया क्या दर्शाता है? क्या सरकार बीएसएनएल को जीवित रखना चाहती है?***

सरकार ने उक्त बैठक में बीएसएनएल में एक पृथक "सब्सिडी टॉवर कम्पनी" बनाने का भी निर्णय लिया है जिसको किसी निपुण व्यक्ति को सौंपना है जिससे कि विकास हो। कौन विकास करेगा? स्पष्ट है *इस टॉवर कम्पनी में कोई स्ट्रेटजिक सहयोगी होगा जिससे बीएसएनएल के शेयर ट्रांसफर हो सके।* यह स्ट्रेटाजिक पार्टनर शेयर की बिक्री करेगा। अब बीएसएनएल के टावर्स का निजी क्षेत्र भी उपयोग करेंगे। उपर्युक्त निर्णय बीएसएनएल के लिए कष्टदायी होगा। टावर्स बीएसएनएल की संपदा है। कुछ लोगों विशेषकर अधिकारियों की सोच है कि इससे बीएसएनएल आर्थिक संकट से बाहर निकलेगा तथा भविष्य में लाभान्वित होगा। परंतु यह वास्तविकता से परे लगता है। एमटीएनएल में तीन होल्डिंग कंपनियां हैं एवं सभी उसके प्रबंधन के अधीन हैं। परंतु कंपनी हानि में है। कैबिनेट निर्णय के अनुसार टावर कंपनी अन्य को सुपुर्द होगा। इन कारणों से बीएसएनएल मजबूत होने के स्थान पर तीव्र *गति से अनिश्चितता की दिशा में अग्रसारित होगा। स्मरण रहे कि बीबीएनएल कंपनी स्थापित हो चुकी है। इसके स्थापना के समय संघ ने चिंता व्यक्त की थी।*

आश्चर्य तो यह है कि बीएसएनएल तथा डीओटी दोनों ने संघ के प्रतिनिधियों से मुद्दे पर गंभीर संवाद नहीं किया है। उनको ज्ञात होना चाहिए कि निगमीकरण के समय में भी कर्मचारियों के हितों को गिरवी नहीं किया गया था। तीन दिनों की हड़ताल के फलस्वरूप सरकार ने पेंशन तथा नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दी थी परंतु 5 अगस्त का कैबिनेट निर्णय दोनों बिंदुओं पर खामोश है। यदि कर्मचारियों का टावर कम्पनी में ट्रांसफर अथवा प्रतिनियुक्ति होती है तो उनकी पेंशन तथा नौकरी की सुरक्षा किस प्रकार होगी? उल्लेखित 5 अगस्त का निर्णय मनमाना तथा एकतरफा है ***जिससे आभास होता है कि सरकार नशे में है। कर्मचारियों को बेबस करने का यह प्रयास है।***

मीडिया में प्रचुर मात्रा में प्रचार हो रहा है कि 5 अगस्त का निर्णय कम्पनी के आर्थिक कष्टों को दूर करने में सहायक होगा। *यह विडंबना तथा भद्दा मजाक है। वास्तविकता तो यह है कि यह पुनर्जीवन के स्थान पर कम्पनी को विनाश की दिशा में ले जाएगी। यदि सरकार वास्तव में बीएसएनएल को पुनः जीवित करने की इच्छुक है तो इसमें खुलासा तथा पारदिर्शता होनी चाहिए।*

आखिर स्पेक्ट्रम के शेष धन की वापसी क्यों नहीं कर रही है। पैसे की वापसी होने पर बीएसएनएल संकट से अवश्य उभरेगा। एवं अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा।

EDITORIAL

Decision to Destroy or Revive?

Years back the BSNL surrendered BWA spectrums with the high hope that the Govt will refund its deposits of more than Rs. 6700/- crores. It was done during UPA-II regime as at the time company was facing extreme financial constraints. Enormous time elapsed but the spectrum deposits money could not be refunded to the PSU. Forced with the situation the company could not pay the license fee to the DOT and requested for adjustment with the deposits. But even today amount is in balance with the Govt. to the tune of Rs. 5000/- crores. This should be returned to BSNL if at all Govt is keen to revive the same.

The Present Telecom Minister had repeatedly declared very loudly that the present NDA Govt will be different than the UPA II and steps will soon be taken to revive the BSNL. Declarations were made and continuing even today also in both the houses of Parliament. But now disquieting and disturbing news are pouring as union Cabinet on 5th August approved for release of a meagre amount of Rs. 196.16 crores only of CDMA air charges. The Govt what to say of extending financial support is avoiding even to return the full money of BSNL. What it reflects? The Govt intends to destroy or revive?

Surprisingly, the Cabinet same day approved the proposal of BSNL/DOT for the formation of a separate “subsidiary Tower Company” reportedly within the entity and to hand over to a person familiar with the development. Obviously there will be strategic partner preferably enjoying Govt's blessings. ***The BSNL presently is fully state owned and now it has to transfer equity shares to Tower Company to facilitate the process of disinvestment and finally to sale.*** The BSNL towers will now be available to private sector also. These decisions will definitely add miseries to the PSU as “BBNL” had already been formed years ago. The future of BSNL is thus being made uncertain instead of strengthening. ***The NFTE has voiced its deep concerns at the time of formation of “BBNL” also.***

Strangely, neither the BSNL management nor the Govt (DOT) considered it appropriate to consult the unions forgetting that the future of employees has not been mortgaged or surrendered even at the time of corpotarisation. The Cabinet decided to pay the pension to employees as per Govt Rules and guaranteed job security after 3 days historic struggle. But the Cabinet decision of 5th August is silent on above two issues viz Pension and job security if employees are Compelled to go and deputed to Tower Company. The decision of 5th August reflects arrogance and arbitrariness of the ***Govt as dialogue has been avoided with the stake Holders. The employees are thus forced to the walls.***

The news are being widely spread that the decision is to alleviate the financial crunch of the PSU. But the fact appears otherwise. It is not for revival but obviously to destroy. There is no guarantee that the Tower company will be under the BSNL Board akin to three holding companies in MTNL. Once towers are transferred there will be almost no asset left with the BSNL. ***The plea that once Tower Co is formed under BSNL Board the PSU's loss will be wiped out needs deep consideration***. Why Govt is not refunding entire spectrum deposits. The PSU can stand on its own leg if BSNL’s money is returned back.